

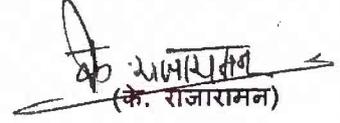
सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.111

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: जून, 2019

कार्यालय जापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मई, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।


(के. राजारामन)

अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23093230/5012

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
13. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
15. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/सलाहकार (आईईआर)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)/सीएए।
16. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
17. डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
18. श्री अरुण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. गार्ड फाइल - 2019

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: मई, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल, 2018 में 4.6% की तुलना में अप्रैल, 2019 में 2.9% थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल, 2018 में 3.6% की तुलना में अप्रैल, 2019 में 3.1% रही।

1.2 भारत का व्यापारिक माल निर्यात अप्रैल, 2018 के दौरान 25.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 0.6% की बढ़त दर्शाते हुए अप्रैल, 2019 के दौरान 26.1 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। भारत का आयात अप्रैल, 2018 में 39.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 4.5 प्रतिशत गिरकर अप्रैल, 2019 के दौरान 41.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। भारत का तेल आयात अप्रैल, 2019 के दौरान 11.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो कि अप्रैल, 2018 में 10.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 9.3 प्रतिशत कम था। व्यापार घाटा अप्रैल, 2018 के दौरान 13.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के घाटे की तुलना में अप्रैल, 2019 में 15.3 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित था।

1.3 भारत का व्यापार घाटा 2017-18 में 162.1 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 6.1 प्रतिशत) से बढ़कर 2018-19 में 183.5 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 6.5 प्रतिशत) हो गया। मुख्य रूप से कुल सेवा अर्जनों और निजी अंतरण प्राप्तियों में बढ़त के कारण 2018-19 में निवल अदृश्य प्राप्ति, उच्च रही। वर्ष 2018-19 में निवल एफडीआई अंतर्वाह 2017-18 में 30.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से 30.9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक रह गया। पोर्टफोलियो निवेश में एक वर्ष पूर्व 22.1 बिलियन अमरीकी डॉलर के अंतर्वाह की तुलना में 2018-19 में 10.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया। वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार में 11.7 बिलियन अमरीकी डॉलर (बीओपी आधार पर) की कमी आई।

1.4 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च, 2019 के 412.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से 7.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की दर्शाते हुए 24 मई, 2019 की स्थिति अनुसार 420.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। अप्रैल, 2019 में 69.47 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए का औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) मई, 2019 माह में 69.77 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर रही।

1.5 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में मार्च, 2018 में 5.3%

की बढ़त की तुलना में मार्च, 2019 में (-)0.1% की बढ़त दर्ज की गयी। अप्रैल-मार्च, 2018-19 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त अप्रैल-मार्च, 2017-18 के दौरान हुई 4.4 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में संचयी आधार पर 3.6 प्रतिशत थी। अप्रैल, 2018 में 4.7 प्रतिशत की तुलना में आठ मुख्य उद्योगों में अप्रैल, 2019 में 2.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल से मार्च, 2018-19 के दौरान मुख्य उद्योगों की बढ़त अप्रैल-मार्च, 2017-18 के दौरान 4.3 प्रतिशत की तुलना में 4.3 प्रतिशत रही।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 22 मई, 2019 के अपने परिपत्र के माध्यम से अभिनवकर्ताओं के विकास मंच के लिए निवेशकों के प्रत्यापन की प्रक्रिया हेतु रूपरेखा जारी की है। इन दिशानिर्देशों में पात्रता, प्रत्यापन की प्रक्रिया, प्रत्यापन की वैद्यता आदि जैसे पहलू शामिल हैं।

(ख) दिनांक 3 मई, 2019 को मॉरिशियस के साथ बीआईपी मुद्दों पर टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा हुई। दिनांक 22 मई, 2019 को तजाकिस्तान के साथ डिजिटल विडियो सम्मेलन के माध्यम से वीआईटी मुद्दों पर चर्चा हुई। दिनांक 24 मई, 2019 को किरगिज के साथ डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीआईटी मुद्दों पर चर्चा हुई।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 8-9 मई, 2019 तक बैंकाक, थाईलैंड में एशिया पॅसिफिक ट्रेड अग्रीमेंट (एपीटीए) कार्य दल की चौथी बैठक में भाग लिया।

(घ) आर्थिक कार्य विभाग ने 28 से 31 मई, 2019 के बीच थाईलैंड में हुई इन्वेस्टमेंट रीजनल कॉपरेशन एण्ड इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) पर कार्यदल के अंतर-सत्रीय बैठक में भाग लिया।

2.2 मार्च, 2019 माह के दौरान निम्नांकित बैठकें आयोजित की गईं:-

- क. वित्त सचिव ने दिनांक 1 से 4 मई, 2019 को नाडी, फिजी में हुई एडीबी की वार्षिक बैठक में भाग लेने हेतु भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किया।
- ख. वित्त सचिव ने दिनांक 17 मई, 2019 को नई दिल्ली में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री सुश्री गीता गोपीनाथ के साथ बैठक की।
- ग. दिनांक 6 मई, 2019 को अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जलवायु संबंधी कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रियों के गठबंधन के संबंध में बैठक हुई।
- घ. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव ने 14 मई, 2019 को ओडिशा तफान "फानी" के लिए आरडीएनए पर विचार विमर्श करने हेतु बैठक की अध्यक्षता की है।
- ङ. श्री संजीव संन्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार ने ब्रसैल्स में दिनांक 15 और 16 मई को निर्धारित फ्रेमवर्क कार्य दल की द्वितीय बैठक में भाग लिया।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य।

5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति

स्वीकृत किए गए: 00

विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित: 08
